



2026:AHC: 59877

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1845 वर्ष 2026

सचिन किशोर और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अनिल कुमार त्यागी, विनय कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

### न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान आवेदन थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर में परिवाद संख्या 3126 वर्ष 2024 (आंचल अग्रवाल बनाम सचिन और अन्य), भा.द.सं. की धारा 323, 392 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मांगने के लिए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जा सके।

3- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें आशंका है कि उन्हें उपर्युक्त वाद में गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, फिर भी विवेचना अधिकारी ने उनके विरुद्ध बिना किसी ठोस साक्ष्य के सतही तरीके से आरोप प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और वे विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया है।

5- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6- वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण, आरोप की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका और वाद के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

7- अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8- पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकों **सचिन किशोर और अमन गुप्ता** की गिरफ्तारी की स्थिति में, विचारण के निष्कर्ष तक उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

- i) आवेदकगण अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- ii) आवेदकगण अभियोजन के गवाहों को डराएंगे-धमकाएंगे या परेशान नहीं करेंगे।
- iii) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होंगे।
- iv) आवेदकगण उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेंगे, जिसका आवेदकों पर आरोप है, या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



9- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

23 मार्च, 2026

एस.अली